Investment by Israeli company on 100 per cent basis

2069. SHRI YERRA NARAYANASWAMY: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Andhra Pradesh Government has sought permission for foreign investment on 100 per cent basis with an Israeli company named M/s. B.H.C. Company, Israel;

(b) the stage of processing of this application at present;

(c) when will this application be cleared; and

(d) the reasons for delay in granting clearance?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) Yes, Sir.

(b) to (d) The approval has already been granted to the company.

Delicesing of industries from the purview of the Industres (Development and Regulation) Act

2070. DR. ALLADI P. RAJKUMAR: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government have recently decided to delicence certain Industries from the purview of Industries (Development and Regulation) Act and also given sweeping powers to the "Navratna" public sector enterprises;

(b) if so, the details of these proposals; and

(c) the criteria followed while selecting the "Navratna" enterprises and the significance of "Navratna" enterprises?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) and (b) Yes, Sir. The Government have delicensed, vide Press Note No. 11 (1997 Series) dated 17th July, 1997, five industriies, namely, (i) Animal fats and Oils; (ii) Tanned or dressed fur skins, chamois leather; (iii) Asbestos and asbestos-based products; (iv) Plywood, veneers of all types and other wood based products such as particle board, medium density fibre board/block board; and (v) Paper and newsprint except bagasse based units.

Navratna enterprises have been granted enhanced financial and managerial autonomy and operational freedom to enable them to become global giants.

(c) The criteria for selecting the enterprises included factors like size, performance, future prospects, potential to become global giants, etc. The benefits accruing to these nine enterprises include substantially enhanced financial powers and greater operational freedom.

Slow down in the production of Passenger cars

2071. SHRI VAYALAR RAVI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that automobile productions especially the passenger cars have came down;

(b) if so, to what extent, details of last three years; and

(c) the reasons for reductions in productions?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

उत्तर प्रदेश के औद्योगीकरण हेतु सरकार के प्रयास

2072. श्री ईश दत्त यादव : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार राज्य के विशषकर उद्योग रहित जिलों और ब्लाकों के औद्योगीकरण हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों का किस प्रकार समर्थन और उनकी सम्पूर्ति कर रही हैं, तत्संबंध. ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या इस प्रयोजनार्थ राज्य के लिए धनराशि विनिर्दिष्ट की गई हैं; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री मुरासोली मारन) : (क) से (ग) केन्द्रीय उद्योग मंत्रालय पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास के लिए तीन योजनाएं चलाता है । ये योजनाएं उत्तर प्रदेश राज्य पर भी लागू होती हैं । ये निम्नलिखित हैं :—

1. **विकास केन्द्र योजना :** इस योजना के अंतर्गत 400–800 हेक्टेयर क्षेत्र में मूलभूत औद्योगिक अवसंरचनात्मक विकास जैसे विद्युत, जल, दूर संचार आदि के विकास सहित विकास केन्द्र स्थापित करने का विचार किया गया है । विकास केन्द्र के कार्यान्वयन में राज्य सरकार द्वारा की गई प्रगति को देखते हुए 10 करोड़ रुपये तक की केन्द्रीय सहायता रिलीज की जा सकती है । उत्तर प्रदेश राज्य के लिये 8 विकास केन्द्रों की योजना है तथा 6 केन्द्रों का पहले ही अनुमोदन हो गया है तथा 2020 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता पहले ही रिलीज कर दी गई है । ये केन्द्र बचौली बुजर्ग (झांसी) बन्धारा (शाहजहांपुर, चौधरपुर (मुरादाबाद), खुर्जा (बुलन्दशहर), मंगरा स्थारिया (जौनपुर), शाहजहांनव (गोरखपुर में हैं दिवियापुर (इटावा) तथा पदमपुर–शिवराजपुर (पौड़ी गढवाल), के संबंध में राज्य चेरकार द्वारा परियोजना रिपोर्ट भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को मूल्य निर्धारण हेतु प्रस्तुत की जानी होती हैं ।

परिवहन राजसहायता योजना : यह योजना देश के पहाड़ी तथा दुर्गम क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक इकाइयों को कच्चा माल तथा निर्मित वस्तुओं के संचालन के लिये परिवहन राजसहायता मुहैया करती है । यह योजना उत्तर प्रदेश के आठ कथित पहाड़ी जिलों में स्थित इकाइयों पर लागू होती है । इस क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयां 50% से 90% तक की दर सीमा में परिवहन राजसहायता का दावा कर सकती ।

3. **एकीकृत अवसरचनात्मक विकास योजना :** इस योजना में लघु उद्योग केन्द्र स्थापित करने का विचार किया गया हैं विशेष रूप से लघु उद्योग तथा लघु इकाइयों को 5.00 करोड़ रुपये के परिव्यय तथा 2.00 करोड़ रु० तक की केन्द्रीय सहायता से अवसरंचना मुहैया कराना हैं । उत्तर प्रदेश राज्य में वर्तमान में 3 राज्य आई आई० डी० केन्द्र गांव उन्नाव (जिला उन्नाव), गांव कोटेवान (जिला मथुरा) तथा यू० पी० एस० आई० डी० क्षेत्र (जिला एटा) स्वीकृत किये गये हैं ।

MoU signed with Harvard Institute of International Development

2073. SHRI MUKESH R. PATEL:
SHRI SANJAY NIRUPAM:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have signed any MoU with the Harvard Institute of International Development.

(b) if so, the terms and conditions of the agreement;

(c) the details of the aims and objectives of the MoU; and

(d) whether it is a fact that this Institute has been blacklisted by US Government earlier and for its dubious activities the US Government has suspended the payment of $14 million?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI MURASOLI MARAN): (a) to (c) The Foreign Investment Promotion Council (FIPC) has entered into an